भारत सरकार
कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3859

जिसका उत्तर 18 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संचालित कोयला खदानें

3859. श्री अनिल फिरोजिया:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और निजी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा संचालित भूमिगत कोयला और धातु खदानों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान भूमिगत कोयला और धातु खदानों में छत गिरने के कारण मृत्यु और गंभीर चोटों से जुड़ी कोई दुर्घटना/घटना हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी घातक और आवंछित घटनाओं से बचने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों को लागू करने के लिए खदान संचालकों को कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए खदान संचालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और निजी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा प्रचालित भूमिगत कोयला और धातु खानों की संख्या निम्नानुसार है:

उद्योग का प्रकार	भूमिगत		मिश्रित (भूमिगत और ओपनकास्ट)	
	कोयला खानों की संख्या	धातु खानों की संख्या	कोयला खानों की संख्या	धातु खानों की संख्या
पीएसयू	226	22	36	1
निजी	12	62	2	5

* आंकड़े अनंतिम हैं।

(ख) : भूमिगत कोयला और भूमिगत धातु खानों में छत गिरने के कारण मृत्यु और गंभीर चोटों से जुड़ी हुई दुर्घटनाओं का ब्यौरा **अनुबंध-I** के रूप में संलग्न है।

(ग) : कोयला खान विनियमन 2017 के तहत, डीजीएमएस स्ट्राटा नियंत्रण, व्यवस्थाबद्ध समर्थन नियम, मैनुअल लोडिंग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने, रूफ बोल्टिंग प्रणाली का समर्थन करने और इसकी शुरुआत करने आदि के लिए परिपत्र के रूप में दिशानिर्देश जारी करता है। डीजीएमएस द्वारा खानों में घातक घटनाओं को कम करने और उनमें कार्यरत कामगारों की सुरक्षा में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) विधायी उपाय:

(क) खान अधिनियम, 1952 और उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए खानों का नियमित निरीक्षण।

(ख) दुर्घटना के कारणों तथा परिस्थितियों का पता लगाने के लिए दुर्घटना और खतरनाक घटनाओं की जांच करना तथा खान प्रबंधन को उपयुक्त उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना।

(ii) मानक सेटिंग का विकास करना।

(iii) खानों में सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने, व्यावसायिक प्रशिक्षण और अन्य प्रशिक्षण प्रदान करने, सुरक्षा सप्ताहों और सुरक्षा अभियानों का आयोजन, बचाव प्रतियोगिता आयोजित करने, सुरक्षा प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी को बढ़ावा देने, जागरूकता और सूचना के प्रसार के रूप में संवर्धनात्मक उपाय करना।

(iv) जोखिम मूल्यांकन तकनीकों को प्रारंभ करना और सुरक्षा प्रबंधन योजना तैयार करना जिसका उद्देश्य जोखिमों को कम करना और मानक प्रचालन प्रक्रियाओं आदि को लागू करने सहित कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

(घ) और (ङ) : खान अधिनियम, 1952 और उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डीजीएमएस द्वारा खानों का नियमित निरीक्षण किया जाता है। दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए दुर्घटना और खतरनाक घटनाओं की जांच करना तथा खान प्रबंधन को उपयुक्त उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना। उक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए खान प्रचालकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

अनुबंध- I

भूमिगत कोयला खानों में छत गिरने (0111) के कारण हुई दुर्घटनाओं का ब्यौरा

राज्य	छत्तीसगढ़		झारखंड		मध्य प्रदेश		ओडिशा	
	मृत	घायल	मृत	घायल	मृत	घायल	मृत	घायल
2019	2	0	0	0	0	1	0	0
2020	1	1	0	1	1	0	1	0
2021	1	0	0	0	1	1	0	0
2022	0	2	0	0	3	0	0	0
2023	0	1	0	0	0	0	0	0
2024	0	1	0	0	0	0	0	0

राज्य	तेलंगाना		महाराष्ट्र		पश्चिम बंगाल	
	मृत	घायल	मृत	घायल	मृत	घायल
2019	1	4	0	0	0	0
2020	1	3	0	0	0	0
2021	6	2	0	0	2	0
2022	0	2	0	0	2	0
2023	1	1	0	1	1	2
2024	0	2	0	0	0	1

भूमिगत धात्विक खानों में छत गिरने (0111) के कारण हुई दुर्घटनाओं का ब्यौरा

राज्य	झारखंड		मध्य प्रदेश		राजस्थान		कर्नाटक		महाराष्ट्र	
	मृत	घायल	मृत	घायल	मृत	घायल	मृत	घायल	मृत	घायल
2019	0	0	3	1	0	1	1	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	2	0	0	0	1	2	0	0

डीजीएमएस द्वारा किए गए निरीक्षणों का ब्यौरा

वर्ष	निरीक्षणों की संख्या	जांच की संख्या	जारी किए गए नोटिस की संख्या	जारी किए गए निषेधात्मक आदेशों की संख्या	शुरू किया गया अभियोजन	जारी किए गए परिपत्र की संख्या
2022	8310	1400	127	216	24	02
2023	9008	1284	233	330	36	02
*2024	6614	1284	169	280	24	07

वर्ष 2024 (अक्टूबर, 24 तक) के आंकड़े अनंतिम हैं।